HI-TECH PIPES

+91-11-48440050
info@hitechpipes.in
hitechpipes.in

07th June, 2020

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex-Bandra(E),
Mumbai-400051,

Symbol: **HITECH**

Sub: News Paper Publication of Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended 31st March, 2021

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the copy of Newspaper publications of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended 31st March, 2021 published in Business Standard English and Hindi (Delhi) edition of 08th June, 2021

Kindly take this information on record and oblige.

Thanking You

For Hi-Tech Pipes Limited

Arun Kumar
Company Secretary

Encl: a/a

गरीब कल्याण योजना नवंबर तक बढ़ी

केंद्र सरकार एनएफएसए के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने पांच किलो चावल या गेहूं देती है

संजीव मुखर्जी

सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अतिरिक्त नि:शुल्क खाद्यान्न देने की योजना की अवधि पांच महीने के लिए बढ़ा दी है। इस योजना के तहत अब गरीब परिवारों को जुलाई से नवंबर तक अतिरिक्त खाद्यान्न मुहैया कराए जाएंगे। कोविड-19 महामारी से देश के ग्रामीण इलाकों में भी जन-जीवन तबाह हो गया है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की अवधि बढ़ाई है। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए पीएमजीकेएवाई-3 के तहत खाद्यान्न वितरण की घोषणा मई और जून के लिए की थी। गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति महीने पांच किलोग्राम चावल या गेहूं देती है। उन्हें अमूमन मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त यह मदद दी जा रही है।

योजना की अवधि बढ़ने के बाद पीएमजीकेएवाई-3 के तहत मौजूदा दरों पर सब्सिडी के मद में सब्सिडी बढ़कर 90,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। इनमें पहले दो महीनों के लिए 26,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी शामिल है। यह रकम वित्त वर्ष 2022 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 180,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी के प्रावधानों के अतिरिक्त होगी।

यह योजना पहली बार अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच मई 2021 में इसे दोबारा शुरू किया गया। हालांकि पिछले वर्ष और इस वर्ष शुरू योजनाओं में एक महत्त्वपूर्ण अंतर है। पहली योजना के तहत दलहन भी वितरित किया जा रहा था लेकिन इस वर्ष गोदामों में पर्याप्त भंडार नहीं होने के कारण केंद्र सरकार दलहन नहीं दे पाएगी।

एक मोटे अनुमानों के अनुसार जुलाई से नवंबर तक पांच महीनों की अवधि के दौरान वितरण के लिए 2 करोड़ टन अतिरिक्त खाद्यान्न की जरूरत होगी। हालांकि सरकार को इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि 1 मई 2021 तक केंद्रीय भंडार में 10 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न जमा थे। पीएमजीकेएवाई-3 के तहत मई और जून में करीब एनएफएसए के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रत्येक महीने करीब 80 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। इस बीच, आंकड़ों के अनुसार 3 जून तक पीएमजीकेएवाई-3 के तहत राज्य भारतीय खाद्य

निगम (एफसीआई) के गोदामों से 64 लाख टन से अधिक खाद्यान्न उठा चुके थे। मई और जून 2021 के लिए पीएमजीकेएवाई के लिए आवंटित खाद्यान्न का यह करीब 80 प्रतिशत है। इनमें 28 लाख टन खाद्यान्न का वितरण 34 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश करीब 55 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को कर चुके हैं। जून 2021 के लिए 2.6 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों के लिए करीब 1.3 लाख टन खाद्यान्न का वितरण हो चुका है। एनएफएस के तहत होने वाले खाद्यान्न के सामान्य वितरण के यह अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2021 में देशव्यापी लॉकडाउन के बीच केंद्र ने पीएमजीकेएवाई-1 योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की थी। शुरू में यह योजना अप्रैल से तीन महीनों के लिए शुरू की थी लेकिन हालात चिंताजनक रहने के कारण इसकी अवधि बढ़ाकर पांच महीने तक कर दी गई। इसके तहत केंद्र ने प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल का वितरण किया। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त यह प्रावधान किया गया था। इसके अलावा सभी जरूरतमंद परिवारों को बिना किसी शुल्क के हरके महीने 1 किलोग्राम दलहन भी वितरित किया गया। पीएम गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत के तहत दो हिस्सों में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 में पीडीएस के तहत आवंटित खाद्यान्न के अतिरिक्त करीब 3.2 करोड़ टन अनाज की आपूर्ति की। सरकार के अनुसार नि:शुल्क अनाज वितरण के लिए अप्रैल, मई और जून के लिए सब्सिडी के मद में करीब 46,061 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने तक बढ़ाने के बाद सरकार पर अतिरिक्त 76,000 करोड़ रुपये सब्सिडी का बोझ पड़ गया है। इस तरह, गरीब कल्याण के तहत दो प्रोत्साहनों के मद में करीब 1.49 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी की जरूरत होगी। हालांकि वास्तविक अनुमानों के अनुसार यह थोड़ी कम यानी 1.05 लाख करोड़ रुपये के करीब रह सकती है। केंद्र सरकार का दावा है कि खाद्यान्न वितरण योजना से महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों को काफी मदद मिली है लेकिन नागरिक समाज के लोगों का कहना है कि यह मदद केवल उन्हीं लोगों को मिली जिनके पास एनएफएसए राशन कार्ड थे।

पीएमजीकेएआई-3 के तहत खाद्यान्न का उठाव और वितरण (3 जून 2021 तक)

मासिक आवंटन	राज्यों द्वारा उठाव**	वितरण का महीना	खाद्यान्न वितरण**	लाभान्वितों की संख्या***	दी गई सब्सिडी
39.6 टन प्रति महीना	63 लाख टन	मई 2021	27.5 लाख टन	5.50 करोड़	8,755 करोड़ रु.
		जून 2021	01.3 लाख टन	2.64 करोड़	473 करोड़ रु.
		कुल	28.2 लाख टन		9,229 करोड़ रु.

स्रोतः खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय

अनलॉक: बाजारों से दूर रहे खरीदार

पृष्ठ 1 का शेष

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पैनासोनिक में भारत एवं दक्षिण एशिया के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्याधिकारी मनीष शर्मा ने कहा कि अर्थव्यवस्था खुलने से बिक्री में सुधार होगा। लेकिन ग्राहकों का मनोबल कमजोर हुआ है और लोग बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। चालू तिमाही में बिक्री हमारे पहले के अनुमान से 60-65 फीसदी कम रह सकती है। पैनासोनिक अपना परिचालनचरणबद्ध तरीके से शुरू कर रही है। गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की अच्छी बिक्री होती है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के कॉर्पोरेट प्लानिंग के उपाध्यक्ष दीपक बंसल ने कहा, 'हम टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव की मांग भी बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि काफी लोग अभी भी घरों से काम कर रहे हैं।' विजय सेल्स के गुप्ता ने भी कहा कि फोन, लैपटॉप जैसे उत्पादों की अच्छी मांग होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि महंगे और नए फोन एवं लैपटॉप की अच्छी मांग देखी गई है। आने वाले समय में भी यह रुझान जारी रह सकता है।

इस बीच मुंबई के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य रिटेलरों ने उम्मीद जताई कि गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खुलने से लोग बाहर आएंगे। हालांकि आज अधिकतर दुकानों में गिने-चुने लोग ही पहुंचे। इनरीच सैलून्स के निदेशक भूपेश डिंगर ने कहा कि कंपनी के कॉल सेंटर में पूछताछ बढ़ गई है। मुंबई में हमारे पास अपॉइंटमेंट की कतार है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों से अच्छी और तेज प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई में हमारे 53 सैलून्स हैं जिनमें से आज 45 खुले थे। आठ मॉल में हैं, लेकिन मॉल बंद रहने की वजह से वे खुल नहीं सके। इनफिनिटी मॉल के मुख्य कार्याधिकारी मुकेश कुमार ने कहा, 'मुंबई में मॉल खोलने की अनुमति नहीं मिलने से थोड़ी निराशा हुई है।' कुमार ने कहा कि अप्रैल-मई में मॉल को करीब 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ऐसे में इसे खोलने की अनुमति देने से नुकसान की कुछ भरपाई करने में मदद मिलेगी।

मामले घटे तो लोगों की बढ़ी आवाजाही

सचिन पी मामबटा और कृष्ण कांत

- संक्रमण में कमी के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे
- कोविड-19 संक्रमण के मामले कम होकर 1 लाख से थोड़े ही ज्यादा

कोविड-19 महामारी के कमजोर पड़ने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। संक्रमण के नए मामलों में कमी के बाद लोगों ने अब अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। लोगों की आवाजाही और यातायात का हाल बताने वाले संकेतक हालात में सुधार के संकेत दे रहे हैं। देश में रोजाना दर्ज होने वाले कोविड-19 संक्रमण के मामले कम होकर 1 लाख के आसपास रह गए हैं। मई के शुरू में रोजाना नए संक्रमण के मामले 4 लाख से अधिक हो गए थे।

लोग अब अपने घरों पर पहले की तरह समय नहीं बिता रहे हैं। उनकी आवाजाही पर नजर रखने वाले गूगल के आंकड़े भी बता रहे हैं कि लोग अपने कार्यालयों की तरफ रुख करने लगे हैं। गूगल उन जगहों पर नजर रखती है जहां लोग महामारी के दौरान जा रहे हैं। ये आंकड़े वास्तविक समय से कुछ दिनों के अंतराल पर जारी होते हैं। ताजा आंकड़े 2 जून तक के हैं। देश के बड़े शहरों में यातायात जोर पकड़ रहा है। टॉम टॉम इंटरनैशनल के अनुसार मुंबई और नई दिल्ली दोनों महानगरों में सड़कों पर लोगों एवं वाहनों की भीड़ देखी जा सकती है।

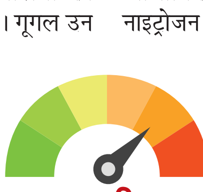

साप्ताहिक संकेतक

उत्सर्जन में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिज़नेस स्टैंडर्ड देश के प्रमुख शहरों में नाइट्रोजन उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करता है। वाहनों की आवाजाही और औद्योगिक गतिविधियों से हवा में नाइट्रोजन डॉइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। दिल्ली में उत्सर्जन पिछले सप्ताह के तुलना में अधिक है, हालांकि यह 2019 के स्तर से अब भी कम है। मुंबई में भी उत्सर्जन में इजाफा हुआ है। बिजली की मांग में भी पहले की तुलना में इजाफा हुआ है। राज्यों में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू करने की अनुमति देने से बिजली की मांग बढ़ना लाजिमी है। वर्ष 2020 की समान अवधि के मुकाबले पिछले सप्ताह बिजली की मांग में 12 प्रतिशत तेजी देखी गई। हालांकि वर्ष 2019 की तुलना में जून 2021 के पहले सप्ताह में बिजली की मांग करीब 9.5 प्रतिशत कम रही है। पिछले दो सप्ताहों के मुकाबले बिजली की मांग में करीब 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

जून 2020 के पहले सप्ताह के मुकाबले भारतीय रेल से माल ढुलाई में भी तेजी देखी गई। थमी गतिविधियां एकाएक शुरू होने से इस वर्ष आंकड़े अधिक प्रतीत हो रहे हैं। माल ढुलाई बढ़ने के साथ ही उनसे प्राप्त होने वाली कमाई भी बढ़ गई है।

गूगल को छोड़कर बाकी सभी आंकड़े रविवार 6 जून तक के हैं। वृहद आर्थिक आंकड़े जारी होने से पहले ये संकेतक जमीनी स्थिति का एक मोटा अंदाजा देते हैं। सरकार अक्सर आंकड़े कुछ देरी के साथ जारी करती है। कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया था। तब से दुनिया भर के विश्लेषक अर्थव्यवस्था के मिजाज का अंदाजा लगाने के लिए इन्हीं संकेतकों का अध्ययन करते आ रहे हैं।

Air traffic recovery likely by third quarter: IndiGo

Airline not to pay dividend for FY21

ARINDAM MAJUMDER
New Delhi, 7 June

IndiGo, India's largest airline, is expecting a recovery in domestic traffic by the third quarter of FY22.

However, the airline expects a longer recovery period for international traffic, which it expects to normalise by Q4 of the financial year.

IndiGo Chief Executive Officer Ronojoy Dutta said while in February passenger traffic had almost reached 80 per cent of what it was in pre-Covid days, the company thought it could reach that stage by the festive season this year.

"We started to see a decline in March and this accelerated in April and May. However, we are now seeing a modest turnaround at the end of May, which has continued in June. We are expecting that with an accelerated vaccine programme, passenger sentiment will recover faster," Dutta said.

The company said that it would not pay any dividend for FY21.


While the company will slow down delivery of new aircraft, it will increase the pace of return of the older A320 Ceo aircraft

The firm, said Dutta, will slow the delivery of new aircraft but will increase the pace of return of older A320 Ceo aircraft.

In FY21, IndiGo took delivery of 46 new aircraft, the highest for any airline across the world.

Chief Financial Officer Jiten Chopra said while the cash burn had gone up due to the second wave, the airline would use sale and leaseback and raise funds through a qualified institutional placement.

IndiGo has managed to maintain its cash position. Its free cash at the end of March stood at ₹7,099 crore vis-à-vis ₹7,444 crore at the end of December. For the same period, total cash, including what is restricted, stood at ₹18,568 crore vis-à-vis ₹18,365 crore, respectively. Analysts point out the various liquidity measures that the airline has taken during the year have helped offset the cash burn during FY21.

The airline's consolidated net losses widened to ₹1,147.16 crore during the March quarter from ₹620.14 crore during the December quarter, and ₹1,194.83 crore in July-September.

IndiGo had reported a loss of ₹871 crore during the March quarter of the previous year.

India had for a while been fairly robust for airlines, thanks to its vast domestic network, though any positivity evaporated with the arrival of the virus, which put brakes on travel. The numbers are staggering, and are likely under-reported. The latest data shows nearly 30 million confirmed Covid-19 cases and more than 349,000 deaths.

According to leading airlines, the number of air passengers per day across India has doubled from a low of 40,000-42,000 a day in May to an average of over 82,000 a day in the first week of June. The upsurge has taken place as states started easing lockdown measures, buoyed by declining infection numbers and case positivity rates.

The uptake of passengers at Delhi airport, the country's largest by capacity and the number of passengers, has also seen an increase in the first few days of June, hitting 30,000 a day, a 66 per cent rise over 18,000 a day throughout May.

CIL's e-auction sales register 52% YoY surge in April, May

SHREYA JAI
New Delhi, 7 June

Coal India (CIL) has witnessed a 52.5 per cent increase in its e-auction sales in the first two months of the current financial year compared to the corresponding period a year ago.

In a statement, CIL said it allocated 21.5 million tonnes (mt) under the five auction windows.

The company said as demand for coal has increased, it registered a 16 per cent premium over the notified price during April-May 2021 compared to 7 per cent in the same period last year.

CIL said the reserve price under all e-auction windows was kept at par with the notified price during the first six months of last financial year.

Out of the total allocated coal volume, the non-power sector accounted for 50 per cent of the booked quantity. This includes steel, iron and cement sectors.


With economic activity rebounding, coal demand from key manufacturing sectors has also increased

With economic activities rebounding, coal demand from key manufacturing sectors has also increased.

E-auction booking by power sector consumers also saw 49 per cent growth over last year. They booked 6.1 mt under 'special forward auction', meant exclusively for them.

The increase is linked to the summer demand from the power sector, which is preparing for the peak season.

Last year, peak demand during the summer months touched a record 180 gigawatt (Gw).

During May 2021, peak power demand saw a 2 per cent year-on-year (YoY) growth.

The spot power market saw its volume growing by 9 per cent YoY.

"Though there is revival in supplies to the power sector, our concern is that there is still a bit of fluctuation in demand. We hope it stabilises soon," said the statement by CIL.

Auction allocation under the 'spot auction' window — ending May 21 — where all coal consumers, including traders, could participate, clocked 4.6 mt, a 35 per cent growth.

"Hopefully, if demand regains stability, we aim to surpass last year's mark with increased add on over the notified price without a let down on supply commitment to the power and non-power sectors," CIL said in its statement.

SBI bets on digital payments start-up Cashfree

SAMREEN AHMAD
Bengaluru, 7 June

State Bank of India has made an undisclosed investment in digital payments and banking technology start-up Cashfree, as the lender looks to promote digital payments. According to sources, the lender has picked up a less than 5 per cent stake in the Bengaluru-based company.

In November last year, Cashfree had raised $35.3 million in a Series B round led by the UK's Apis Growth Fund II.

"The investment from India's largest bank shows its trust in Cashfree's innovation and the way we are rapidly scaling up the payments business," said Akash Sinha, Co-Founder and CEO, Cashfree.

"This also underscores Cashfree's role towards building a payments ecosystem that enables the fastest and easiest way to collect payments and make payouts for growing businesses," he added. The company will use the fund to innovate, scale up, and build its payments infrastructure. Cashfree provides a full-stack payments solutions platform enabling businesses to accept and disburse payment online through a single integration.

Skoda commences production of upcoming SUV

Skoda Auto India on Monday said it has commenced production of its upcoming SUV KUSHAQ, the deliveries of which are scheduled to commence in July.

The model, which is the first production car as part of the company's India 2.0 project, is being rolled out from the Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd (SAVWIPL) plant in Chakan, Pune.

PTI